The stocks of pressure par-boiled IR-8 rice purchased by the F.C.I. are gradually being disposed of in Food For Work Programme, in relief distribution and some quantities have also been exported.

There is nothing wrong with the technique as such and if the rice millers follow the correct method, the rice is acceptable to the consumers.

Steps have been taken to educate the millers in the correct technique of making par-boiled rice through pressure of steam. Teams of experts have visited these two States and demonstrated the correct procedure. Pamphlets explaining the system in detail have also been distributed and the quality Control Teams of both the States as well as the Central Government are keeping a close watch on the process adopted by the millers. These efforts have shown results and the quality of rice made by this method of par-boiling has improved.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न और धन का आबंटन

960. **प्रो० रूपचन्द्र पाल :**
श्री जमीलुर्रहमान :
श्री के० मालन्ना :
श्री समर मुखर्जी :

क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980–81 के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को, राज्यवार, खाद्यान्न की कितनी मात्रा और कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का विचार है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को राज्यवार अब तक खाद्यान्न की कितनी मात्रा और कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कार्यक्रम की गति बहुत धीमी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम की गति में कब तेजी लाई जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके मुकाबले में, कार्यक्रम के लिए कुल 21 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा (जिसमे वर्ष 1979–80 की उपयोग में न लाई गई 7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा तथा चालू वर्ष के दौरान आवंटित 14 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा शामिल है) वंटित की जा चुकी है । इसके अलावा, सामग्री घटक के लिए 70 करोड़ रुपये की धनराशि तथा मजदूरी घटक के लिए 22.40 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है ।

(ख) विभिन्न राज्यों को अब तक आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा नकद निधियों को दर्शाने वाले विवरण 1 तथा 2 सभा पटल पर रख दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिय** संख्या एल–टी—1417/80] ।

(ग) व (घ) कार्यक्रम के अन्तकर्गत लगभग 10 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा पहले ही उपयोग में लाई जा चुकी है । इस प्रकार उपयोग की गति को धीमी नहीं कहा जा सकता है ।

Telephone Facilities in Bombay

961. DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a long list of people on the waiting list for allotment of a